Year	Total tirade (Indian & Foreign Liies)	Indian Lines	Percentage Share
	(MILLION TONNES)		(%)
1992-93	1ZL30	42.66	34.90
1993-94	136.97	46.07	33.60
1994-95	146.55	42.02	28.70
1995-96	166.10	46.00	27.80
1996-97	(Not Available)		

(b) The main reasons for the shortfall are as under:

(i) Indian shipping tonnage has not increased at a matching rate with the volume of cargo. As compared to 1992-93 the volume of cargo increased by 43.8 million tons in 1995-96, i.e. increase of about 36%. However, the Indian shipping tonnage increased only by 12% during the same period.

(ii) Indian shipping companies have been given freedom to trade their vessels as per their commercial judgement in cross trade without any obligation to carry Indian cargo.

(iii) Inadequate fiscal and financial incentives.

(c) The details of ship acquisition during the last five years is as under-

Year	No. of vessels	G.R.T.
1.4.1993	440	62,76,618
1.4.1994	442	62.7U,38$
1.4.1995	451	65.55,149
1.4.1996	480	71,00,253
1.4.1997	481	69,15,080

The 8th Plan target of reaching 7 million GRT was achieved in 1996 itself.

However, there has been a slight drop in the tonnage position during 1996-97 on account of slow replacement of the vessels which have been scrapped.

निजी क्षेत्र द्वारा कांडला पत्तन में निवेश के लिए प्रस्ताव

118. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा कांडला पत्तन में निवेश करने से संबंधित निजी क्षेत्र के कुल कितने प्रस्तावों को अब तक स्वीकृति प्रदान की गई हैं.

(ख) किन-किन निजी क्षेत्रों ने इस संबंध में निवेश करने के लिये अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और निवेश की कुल धनराशि क्या हैं तथा इस संबंध मे निवेश के लिए उक्त पत्तन के किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया हैं.

(ग) उक्त निवेश के परिणामस्वरूप कांडला पत्तन के विकास और विस्तार की गति में किस सीमा तक वृद्वि होगी

(घ) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कोई समयबद्व कार्यक्रम बनाया हैं और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) कांडला पत्तन में निजी निवेश के बारे में सरकार ने अभी तक चार प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

	परियोजना का नाम	निजी क्षेत्र का नाम	निवेश हेतु राशि
1.	4 इलैक्ट्रिक ब्हार्फ क्रेनों को पट्टे पर देना	मैं. मुकून्द लि. मुम्बई मैं. ए बी जी हैवी इंडस्ट्रीलज लि., मुम्बई	20.00 करोड़े

	परियोजना का नाम	निजी क्षेत्र का नाम	निवेश हेतु राशि
2.	कांडला में नौवें और दसवें शुष्क कार्गो वर्थों का निर्माण	मैं.ए सी टी शिपिंग लि., गोधीधाम मै. पंजाब स्टेट कंटेनर एंड वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन लि. चडीगढ़ मैं. मारूति उघोग लि. चंडीगढ़ मै. प्रीसियश शिपिग (मारिशस) लि. मारिशस	150.00 करोड़
3.	वदीनगर में रिफायनरी हेतु पत्तन सम्बद्व सुविधाओं का सृजन	मै. एस्सार आयल लि.	560.00 करोड़

(ग) (i) बर्थ सं. 6 पर बल्क और ब्रेक बल्क कांग की यंत्रीकृत हैडलिंग हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी से बतव में प्रति बर्थ आऊटपुट दुगनी हो गई हैं जिसके फलस्वरूप जलयानों के टर्न-राऊड समय में तेजी आई हैं।

(ii) मैं. इंडिन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. द्वार आबद्व जैट्टी पूरी कर लिए जाने के बाद तरल कांगों की हैडलिंग के मामले में पत्तन की क्षमता में 3 मिलियन टन की बढोत्तरी होगी।

(iii) मैं. भारतीय तेल निगम और हिन्दुस्तान मिलियम कारपोरेशन लि. द्वारा आभासी जैट्टी के निर्णय के बाद कांडला में 3.5 मिलियम टन पी ओएल वदों की अतिरिक्त "थ्रू पुट" हैडल की जा सकेगी

(IV) निजी क्षेत्र द्वारा 4 इलैक्ट्रानिक क्रेन कांडला पत्तन कोट्टे पर दिए जाने के बाद कांडला पत्तन न्यास प्री कार्गो के स्वरूप के आधार पर 9 लाख टन आंत आउटपुट प्राप्त कर सकेगा।

नौवें और दसवें कार्गो बर्थ के पूरा हो जाने पर पत्तन क्षमता में तत्काल 1.5 मिलियन टन क बढोतरी होगी, जो बाद के 4 वर्षो में बढ़कर 2.4 मिलियन टन हो जाएगी।

(२० एस्सार आवल लि. के प्रस्ताव में वदीनार में 1 मिलियन टन कच्चे तेल पी ओ एल उत्पादों की हैडलिग परिकल्पना की गई हैं।

(घ) और (ड.) निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

Port-Projects pending for Implementation

119. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state;

(a) the details of the Port-projects pending for implementation with Government as on today;

(b) the reasons for the pendency; and

(c) by when they will be cleared?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKAT-RAMAN): (a) As on date, the following port projects are pending Government approval:

(1) Modernisation of MOT Berths at Mumbai Port.

(2) Further Extension of Container Terminal at Chennai Port.

(3) Capital Dredging at Tuticorin Port.

(b) These projects are required to be processed for approval of the Public Investment Board and Cabinet Committee on Economic Affairs after consulting various Ministeries[7] Departments viz. Finance, Environment and Planning Commission, which takes some time, before Government sanction is issued.